खबरों में रहे स्टॉक

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

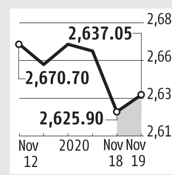

शेयर पुनर्खरीद के लिए 28 नवंबर की तारीख निर्धारित की है

₹ 2625.9 पिछला बंद भाव

₹ 2637.1 आज का बंद भाव

▲ 0.4 %

जीपीटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स

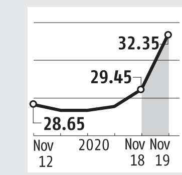

कंपनी ने एचआरबीसी से 163 करोड़ रुपये का ठेका हासिल किया है

₹ 29.5 पिछला बंद भाव

₹ 32.4 आज का बंद भाव

▲ 9.8 %

एसीसी

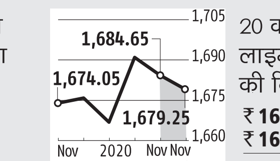

20 करोड़ रुपये में नैशनल लाइमस्टोन कंपनी प्राइवेट की बिक्री

₹ 1684.7 पिछला बंद भाव

₹ 1679.3 आज का बंद भाव

▼ 0.3 %

जीटीपीएल हैथवे

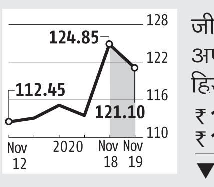

जीटीपीएल स्पेस सिटी में अपनी पूरी 61.50 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची

₹ 124.9 पिछला बंद भाव

₹ 121.1 आज का बंद भाव

▼ 3.0 %

विप्रो

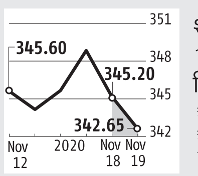

शेयर पुनर्खरीद के लिए 11 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है

₹ 345.2 पिछला बंद भाव

₹ 342.7 आज का बंद भाव

▼ 0.7 %

संक्षेप में

पी-नोट्स के जरिये अक्टूबर में निवेश बढ़ा

भारतीय बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के जरिए निवेश अक्टूबर में बढ़कर 78,686 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह पी-नोट्स के जरिए निवेश का 14 माह का उच्चस्तर है। वैश्विक स्तर पर तरलता की स्थिति अच्छी होने तथा घरेलू मोर्चे पर सरकार द्वारा किए गए उपायों से पी-नोट्स के जरिये निवेश बढ़ा है। पी-नोट्स पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा ऐसे विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं, जो पंजीकरण कराए बिना भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें पूरी जांच-पड़ताल की प्रक्रिया से गुजरना होता है। सितंबर के अंत तक यह निवेश 69,821 करोड़ रुपये था। अगस्त, 2019 के बाद पी-नोट्स के जरिये निवेश का यह सबसे ऊंचा स्तर है। उस समय पी-नोट्स के जरिए निवेश का आंकड़ा 79,088 करोड़ रुपये रहा था। सितंबर, 2020 में इस मार्ग से निवेश घटा था। हालांकि, मार्च से यह लगातार बढ़ रहा था। *भाषा*

सेबी को 147 पदों के लिए आवेदन मिले

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में 147 वरिष्ठ अधिकारियों के रिक्त पदों के लिए 1.4 लाख लोगों ने आवेदन किया है। नियामक ने इस साल मार्च में इन खाली पदों के लिए आवेदन मांगे थे। सेबी अपने कामकाज में तेजी लाने तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना चाहता है। *भाषा*

प्राप्त हुईं संशोधित पेशकश पर

आम सहमति से ही बढ़ेंगे लेनदार

देव चटर्जी
मुंबई, 19 नवंबर

दीवान हाउसिंग फाइनैंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) के लेनदारों को चार संशोधित पेशकशें मिली हैं लेकिन लेनदारों ने इन पेशकशों को अभी तक खोलकर देखा नहीं है और आपसी आम सहमति चाह रहे हैं कि कैसे बोली प्रक्रिया पर आगे बढ़ा जाए। कंपनी की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज को भेजी सूचना में ये बातें कही गई है।

बयान में कहा गया है, दिलचस्प रूप से सीओसी को एक बोलीदाता से ईमेल में अटैचमेंट मिला है, जिसे अभी तक खोला नहीं गया है। एक्सचेंज को भेजी सूचना में कहा गया है, प्रशासक को कुछ निश्चित अटैचमेंट के साथ एक आवेदक का ईमेल मिला है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इसे अभी इसे खोला नहीं गया है। बैठक में सीओसी ने अंतिम समाधान योजना और ईमेल को तब तक नहीं खोलने का फैसला लिया जब तक कि सीओसी इस मामले पर सामूहिक रूप से किसी आमसहमति पर न पहुंच जाएं।

एक बैंकिंग सूत्र ने कहा, ईमेल में संशोधित पासवर्ड संरक्षित पेशकश है, जिसे पीरामल एंटरप्राइजेज ने भेजा है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी पेशकश लीक हो जाए। पीरामल ने दूसरे दौर में खुदरा लोनबुक के लिए बोली संशोधित कर 25,000 करोड़ रुपये की थी, जिसमें सात साल तक भुगतान करना शामिल है और इसके साथ 3,000 करोड़ रुपये का ब्याज भी है। यह पेशकश अमेरिकी फंड ओकट्री की तरफ से डीएचएफएल की पूरी परिसंपत्ति की पेशकश के समान है, जिसने सात साल तक भुगतान की पेशकश की है।

DHFL
प्रॉपर्टी और होम लोन मेला
100+ अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज
CAPITAL GREENS

पीरामल एंटरप्राइजेज ने पासवर्ड से बंद कर बोली सौंपी है

पीरामल समूह के लिए डीएचएफएल की खुदरा लोनबुक को खरीदना अहम है क्योंकि उसका स्थायी नकदी प्रवाह होलसेल बुक का पूरक बनेगा, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी से मुश्किलों का सामना कर रहा है।

पीरामल व ओकट्री की पेशकश में 12,000 करोड़ रुपये देने की बात है, जो उनकी पेशकश का हिस्सा है। बैंकर चाहते हैं कि बोलीदाताओं से और अग्रिम नकदी मिले। ओकट्री ने भी लेनदारों से कहा है कि वह प्रक्रिया से बाहर निकल जाएगी अगर उसे डीएचएफएल में किसी अन्य तरह की कमियां नजर आएंगी। बैंकिंग सूत्र ने कहा, आईबीसी प्रक्रिया में शामिल होने वाले प्राइवेज इक्विटीज को लेकर लेनदारों का अनुभव खराब रहा है क्योंकि पेशकश कर वे बाद में उसे वापस ले लेते हैं जब उन्हें ऊंची बोलीदाता घोषित किया जाता है। ओकट्री की शर्तों पर वे कानूनी सलाह ले रहे हैं। ओकट्री, पीरामल और अदाणी के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी करने से मना कर दिया।

लेनदार डीएचएफएल के स्वामित्व वाले बीमा उद्यम की बिक्री सबसे पहले पूरा करने की योजना बना रहे हैं ताकि यह मूल कंपनी की बिक्री पर असर न डाले। अगर कोई विदेशी कंपनी डीएचएफएल की हिस्सेदारी खरीदती है तो उसे बीमा नियामक की मंजूरी शायद नहीं मिलेगी क्योंकि यह बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा का उल्लंघन करेगा। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस में डीएचएफएल की हिस्सेदारी 49 फीसदी है जबकि बाकी विदेशी साझेदार के पास है। अदाणी समूह ने प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को तब चौंका दिया जब उसने थोक परिसंपत्ति की बजाय पूरे डीएचएफएल के लिए बोली लगाने का फैसला लिया। हालांकि पहले दौर में उसने सिर्फ थोक परिसंपत्ति के लिए ही बोली लगाई थी। अदाणी समूह ने बैंकों को 31,250 करोड़ रुपये की पेशकश की है जबकि ओकट्री ने 31,000 करोड़ रुपये की। चौथी बोलीदाता एससी लोवी की बोली थोक बुक के लिए कई शर्तों के साथ है। तीसरे दौर में उसकी बोली की जानकारी नहीं मिल पाई है।

कंपनी के खिलाफ 95,000 करोड़ रुपये का दावा करने वाले डीएचएफएल के लेनदार जल्द से जल्द प्रक्रिया समाप्त करना चाहते हैं क्योंकि बोर्ड पर आरबीआई के नियंत्रण और प्रशासक की नियुक्ति का करीब एक साल पूरा हो चुका है।

आईफिन अपनी कॉरपोरेट ऋण बुक बेचेगी

बीएस संवाददाता
मुंबई, 19 नवंबर

इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) की गैर-बैंकिंग वित्तीय इकाई आईएलऐंडएफएस फाइनैंशियल सर्विसेज (आईफिन) ने नीलामी के जरिये अपनी एक्सटर्नल कॉरपोरेट लोन बुक बेचने की योजना बनाई है, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होगी।

कंपनी ने एक बयान में कहा है कि करीब 5,000 करोड़ रुपये मूल्य के कॉरपोरेट ऋणों की नीलामी की जाएगी। एक्सटर्नल ऋण बुक में उन 70 कंपनियों के लिए ऋण शामिल हैं जो ऋणदाता के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) में तब्दील हो गए हैं। इसके अलावा, यह बिक्री नकदी के आधार पर पूरी होगी।

आईफिन की 18,000 करोड़ रुपये की प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां हैं, जिनमें समूह इकाइयों और बाहरी कंपनियों के लिए दिए गए ऋण भी शामिल हैं।

आईफिन की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2019 तक आईफिन की ऋण बुक 12,945 करोड़ रुपये थी, जिसमें 96 प्रतिशत गैर-निष्पादित थी। आईएलऐंडएफएस बोर्ड द्वारा एनसीएलएटी के समक्ष पेश एक रिपोर्ट के अनुसार, सकल एनपीए कुल ऋणों की करीब 97 प्रतिशत (नवंबर 2019 के अंत में) थीं। बोर्ड ने एक हलफनामे में करीब 30 बाहरी कर्जदारों और समूह इकाइयों से 1,380 करोड़ रुपये वसूलने का दावा किया था।

अब तक (सितंबर 2020 के अंत तक) नए बोर्ड ने समूह के 19,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऋण को सुलझा लिया है, जो 26,440 करोड़ रुपये के लक्ष्य से काफी कम है। शेष 7,300 करोड़ रुपये के ऋण बाद की तिमाहियों में हासिल किए जाएंगे। जुलाई-सितंबर तिमाही में, बोर्ड 1,460 करोड़ रुपये के कर्ज सुलझाने में सफल रहा था। बोर्ड अब दिसंबर 2020 तक 13,200 करोड़ रुपये के अन्य ऋणों का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है।

उदय कोटक के नेतृत्व वाला आईएलऐंडएफएस अब 56,300 करोड़ रुपये के ऋण का समाधान निकालने की संभावना तलाश रहा है, जो समूह के कुल ऋणों का 50 प्रतिशत से ज्यादा है।

विकास प्रोपेंट एण्ड ग्रेनाईट लिमिटेड VIKAS

कॉर्पोरेट कार्यालय: एफ–88/89, उद्योग विहार, रिको इंडस्ट्रीयल एरीया, श्रीगंगानगर–335002 (राजस्थान)
सीआईएन: L14100HR1994PLC036433
पंजीकृत कार्यालय: हिसार रोड़, सिवानी-127046 (हरियाणा)
टेलि: 0154-2491319, **फैक्स:** 0154-2494361
ई–मेल आईडी: office@vikasgranariers.in
हमारी वेबसाईट पर जाएँ: www.vpgl.in या www.vikasproppantandgraniteltd.in

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनिमय 2015 (सूचीयन विनियमन) के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 25 नवम्बर, 2020 को उपरांह 03:30 बजे कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय एफ–88/89, उधोग विहार, रिको, श्रीगंगानगर में 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु आयोजित की जायेगी।

बोर्ड की आज्ञानूसार
विकास प्रोपेंट एण्ड ग्रेनाईट लिमिटेड

हस्ता/–
(कामिनी जिन्दल)
निदेशक

तिथि : 19/11/2020
स्थान : श्रीगंगानगर

SBI

कॉर्पोरेट सेंटर, तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह,
2री मंजिल, टॉवर “4”, द आर्केड बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
कफ परेड, मुंबई – 400 005.

ई-नीलामी के माध्यम से बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई को वित्तीय आस्तियों की बिक्री

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई को वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने हेतु बोलियां आमंत्रित की जाएंगी । ऐसी वित्तीय आस्तियों को खरीदने के इच्छुक बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई बैंक के साथ एक गैर–प्रकटीकरण करार निष्पादित करने के पश्चात, यदि पहले निष्पादित नहीं किया हो, बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं । बैंक द्वारा समय–समय पर ऐसी वित्तीय आस्तियों को प्रदर्शित किया जाएगा । बैंक के साथ गैर–प्रकटीकरण करार का निष्पादन करने और अन्य पूछताछ के लिए, ऐसे इच्छुक बैंक/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई ई–मेल आईडी **dgm.sr@sbi.co.in** पर संपर्क कर सकते हैं ।

भारतीय स्टेट बैंक अपनी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की प्रस्तावित बिक्री के लिए बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है । इनमें ₹103.59 करोड़ की कुल बकाया राशि वाली (01) वित्तीय आस्ति शामिल हैं । पात्र भावि बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ‘‘रुचि की अभिव्यक्ति’’ के रूप में अपनी इच्छा को सूचित करें । कृपया बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** पर जाएँ । अधिक जानकारी के लिए SBI In the news > Auction Notice > ARC AND DRT लिंक पर क्लिक करें।

जारीकर्ता
उप महाप्रबंधक
(एआरसी)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 20-11-2020

बिज़नेस स्टैंडर्ड
दिल्ली संस्करण

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, उ. प्र. से मुद्रित एवं नेहरु हाउस, 4 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित
संपादकः कैलाश नौटियाल

आरएनआई न० WBHIN/2008/24333
पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं1
टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें..
सुश्री मानसी सिंह
हेड कस्टमर रिलेशन्स
बिज़नेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच,
पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013
ई मेल.. subs_bs@bsmail.in
या 57007 पर एसएमएस करें SUB BS

डिसक्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है1 बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए।
मै0 बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरु की जाएगी।

कोई हवाई अधिभार नहीं

त्वरित समाधान से वित्तीय स्थायित्व बनाए रखने में मिलेगी मदद

अभिजित लेले
मुंबई, 19 नवंबर

वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स (एसऐंडपी) ने आज कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक को पटरी पर लाने के लिए सिंगापुर के डीबीएस बैंक पर विचार करना विदेशी इकाइयों की बैंकिंग परिसंपत्तियों पर नियंत्रण की भारतीय रिजर्व बैंक की इच्छा प्रदर्शित करता है। पहले देसी संस्थानों पर जोर दिया जाता रहा है। इस साल निजी क्षेत्र के येस बैंक को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक व अन्य भारतीय बैकों को पूंजी के सहारे के लिए चुना था। मुश्किल में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक के त्वरित समाधान से बैंकिंग व्यवस्था में वित्तीय स्थायित्व बनाए रखने में मदद मिलेगी। एक अन्य रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा कि सिंगापुर की डीबीएस समूह की भारतीय इकाई की तरफ से लक्ष्मी विलास बैंक का प्रस्तावित अधिग्रहण तत्काल डीबीएस की क्रेडिट रेटिंग पर असर नहीं डालेगा क्योंकि यह पर्याप्त रूप से बहुत बड़ा नहीं है।

Carrier

कैरियर एयरकंडशिनिंग एंड रेफ्रिरेजशन लि.
CIN: U74999HR1992FLC036104
पंजी कार्या. : नरसिंह, खिड़की धौला पोस्ट, गुड़गांव 122 001, हरियाणा
Phone: +91-124-4825500, **Fax:** +91-124-2372230
Website: www.carrierindia.com, **Email:** secretarial@carrier.com

28वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

प्रिय सदस्य,

1. कंपनी के सदस्यों की अठाइसवीं वार्षिक आम बैठक (‘‘एजीएम’’) एजीएम बुलाने की सूचना में वर्णित व्यापार का लेन–देन करने के लिए निगमित मामलों के मंत्रालय (‘‘एमसीए’’) द्वारा जारी साधारण परिपत्र नं. 14/2020, 17/2020) और 20/2020 क्रमश दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 5 मई 2020 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 (‘‘अधिनियम’’) और उसके अंतर्गत बने नियमों के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो क्रांफ्रेसिंग (‘‘वीसी’’)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (‘‘ओएवीएम’’) के माध्यम से बुधवार 16 दिसम्बर, 2020को दोपहर 2.30 भारतीय मानक समय पर आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के लिए की जाएगी।
2. एमसीए के उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय विवरण, बोर्ड कर रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट व उसमें जोड़े जाने वाले आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को मेल द्वारा भेज जा चुकी है जिनके मेल कंपनी या डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.carrier.com/building-solutions/en/in/investor/** और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।
3. **ई–मेल रजिस्टर/अपडेट करने का तरीका :**
भौतिक रूप मे शेयर रखने वाले सदस्य जिनके मेल कंपनी और/या कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ रजिस्टर/अपडेट नहीं हैं, वे अपने मेल रजिस्टर/अपडेट करा सकते हैं और **secretarial@carrier.com** पर कंपनी और/या **admin@mcsregistrars.com** पर कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट को मेल भेजकर निम्न दस्तावेजों की स्कैनड प्रति भेजकर वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा 28वीं एजीएम से जुड़ने के लिए लॉग–इन विवरण, 28वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
1) अपना नाम, फोलियो नंबर व पता वर्णित करते हुए एम हस्ताक्षरित अनुरोध प्त्र
2) पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति
3) सदस्य के पते के लिए किसी दस्तावेज (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान कार्ड, पासपोर्ट) की स्व–सत्यापित प्रति
गैर भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके मेल डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ रजिस्टर/अपडेट नहीं हैं, वे अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने मेल रजिस्टर/अपडेट करा सकते हैं।
4. ई–वोटिंग द्वारा वोट डालने का तरीका : 4
कंपनी ने 28वीं एजीएम की सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग (‘‘रिमोट ई–वोटिंग’’) की सुविधा दी है। कंपनी ने 28वीं एजीएम (‘‘ई–वोटिंग’’) के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा वोटिंग करने की सुविधा भी दी है। रिमोट ई–वोटिंग/ ई–वोटिंग’व वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया जल्दी ही भेजी जाएगी और कंपनी की वेबसाइट **www.carrier.com/building-solutions/en/in/investor/** पर भी उपलब्ध होगी।
सदस्य रिमोट ई–वोटिंग व ई–वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना के लिए नोट में दिए गए निर्देशों को अपनाकर लॉग–इन क्रेडेंशियल जनरेट कर सकते हैं। लॉग–इन क्रेडेंशियल वीसी/ओएवीएम के द्वारा एजीएम में भाग लेने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के द्वारा एजीएम से जुडने की प्रक्रिया सहित एजीएम की सूचना में वर्णित सभी नोट व एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग व ई–वोटिंग के लिए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसी भी सहायता के लिए कृपया कंपनी के सचिव विभाग, कैरियर एयरकंडीशिनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड, खिड़की धौला पोस्ट, नरसिंहपुर, गुड़गांव–122001, ई–मेल : **secretarial/carrier.com** और/या एमसीएस शेयर हस्तांतरण एजेंट लि., एफ–65, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020 ई–मेल : **admin@mcsregistrars.com**को कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट को लिख सकते हैं। सदस्यों को कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ सभी संचार में फोलियो नंबर लिखना आवश्यक है।

कैरियर एयरकंडीशिनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड,
हस्ता./–
चिराग बैजल
प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : 08465289

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 19 नवम्बर, 2020

बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बना सकता है रिजर्व बैंक का समाधान

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 19 नवंबर

प्रमुख ऋणदाता येस बैंक, पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक), और लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) परेशानी से ग्रसित नामों में शामिल रहे हैं।

जब बैंकों पर गहरा संकट आया, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उनके लिए सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंक के साथ विलय के आजमाए हुए उपायों पर अमल नहीं किया। इसके बजाय उसने इन्हें बचाने के लिए अलग दृष्टिकोण को अपनाया। येस बैंक के मामले में, भारतीय स्टेट बैंक ने स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ 49 प्रतिशत हिस्सेदारी (निजी ऋणदाताओं द्वारा छोटी हिस्सेदारी खरीदे जाने के साथ) ली। सितंबर 2019 में मोरेटोरियम के दायरे में लाए गए पीएमसी बैंक ने इस महीने एक छोटे वित्त बैंक (एसएफबी) में तब्दील होने के लिए निवेशकों से आवेदन स्वीकार कर सभी को चौंका दिया।

उसने ऐसे सहकारी बैंकों को एसएफबी में तब्दील होने की अनुमति के लिए इस साल आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर अमल किया। यदि अच्छी गुणवत्ता वाले निवेशक दिलचस्पी दिखाते हैं तो पीएमसी बैंक एक दिलचस्प परीक्षण मामला बन सकता है। पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं के पास अपनी जमाओं को इक्विटी में तब्दील करने का विकल्प है। इसी तरह, एलवीबी के लिए समाधान कम महत्वपूर्ण नहीं है। जहां नियामक ने भारत में मौजूद विदेशी बैंकों को 10 प्रतिशत हिस्सा (या गंभीर संकट की स्थिति में ज्यादा) खरीदने की अनुमति दी है, वहीं एलवीबी को डीबीएस बैंक इंडिया के साथ विलय के प्रस्ताव इस तरह का पहला मामला होगा। मैक्वेरी कैपिटल के सुरेश गणपति ने कहा, ‘पिछले समय में आरबीआई के प्रयासों को देखते हुए हम इस कदम से आश्चर्यचकित हुए हैं।’

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

- चाहे येस बैंक, पीएमबी बैंक हो या एलवीबी, वर्ष 2020 में नियामक ने विफल बैंकों को बचाने के लिए बाजार-केंद्रित समाधानों पर जोर दिया है
- पीएमसी बैंक ने इस महीने एक छोटे वित्त बैंक (एसएफबी) में तब्दील होने के लिए निवेशकों से आवेदन स्वीकार कर सभी को चौंका दिया

एनविजन कैपिटल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी नीलेश शाह के लिए संस्थागत दिलचस्पी बरकराररखने के मकसद के साथ बाजार-केंद्रित समाधान बैंकों में निवेशकों को आकर्षित करने की राह में दीर्घावधि उपाय होगा।

31 दिसंबर 2019 तक विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की 28.5 प्रतिशत और गैर-संस्थागत निवेशकों की 43 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ येस बैंक बड़ी हिस्सेदारी वाला बैंक था।

विश्लेषकों का कहना है कि जब बैंक को मोरेटोरियम के दायरे में लाया गया है तो इक्विटी निवेशकों का हित आरबीआई की शीर्ष चिंता नहीं होगा।

एलवीबी के मामले में, शाह का कहना है कि स्वामित्व पैटर्न येस बैंक स्टाइल के सॉल्युशन जैसा नहीं है। वह कहते हैं, ‘यदि इक्विटी निवेशकों को जोखिम पूंजी में रखा जाता है तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा।’ एलवीबी की नकारात्मक नेटवर्थ स्थिति भी सूचीबद्धता समाप्त किए जाने के निर्णय को तर्कसंगत ठहराती है। शाह कहते हैं, ‘डीबीएस बैंक इंडिया एक विनियमित संस्थागत निवेशक है जो एलवीबी के जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करेगा।’ हालांकि क्या इन खास प्रयासों का परिणाम निकलेगा। येस बैंक बोर्ड में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग विश्लेषक अनंत नारायण का कहना है कि इन समाधानों का परिणाम सामने आने में समय लगेगा।

नारायण नए समाधानों के लिए आरबीआई के प्रयासों की सराहना करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि यह विलय मोरेटोरियम के बगैर नहीं होगा। उनका कहना है, ‘चाहे येस बैंक हो या एलवीबी, इसे लेकर बाजार दिलचस्पी कायम थी। फिर भी, आरबीआई के हस्तक्षेप के बगैर कुछ नहीं हुआ।’ वह सवालिया अंदाज में कहते हैं कि यदि निवेशक बैंकों की गुणवत्ता को लेकर आशंकित हों तो सौदे स्वाभाविक तौर पर कैसे हो सकते हैं।

फिर भी, उन्हें उम्मीद है कि इन छोटे कदमों से बेहद चर्चित फाइनैंशियल रिजोल्यूशन ऐंड डिपोजिट इंश्योरेंस (एफआरडीआई) बिल के अस्तित्व में आने में मदद मिल सकेगी।

बाजार विस्तार की तैयारी में अपोलो हॉस्पिटल्स

टीई नरसिम्हनन
चेन्नई, 19 नवंबर

कोलकाता की अपोलो ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल लिमिटेड (एजीएचएल) में आईएचएच हेल्थकेयर (आईएचएच) की हिस्सेदारी हासिल करने के बाद चेन्नई की अपोलो हॉस्पिटल्स को अब देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में विस्तार के लिए कुछ और अधिग्रहण की तलाश है। इस अस्पताल श्रृंखला को हाल ही में 1,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली है और इसके कुछ भाग का का वित्त पोषण अधिग्रहण में किया जाएगा।

अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की प्रबंध निदेशक सुनीता रेड्डी ने कहा कि हालांकि फिलहाल शायद वे नई परियोजना शुरू करने पर विचार न करें, लेकिन मुख्य रूप से देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अपोलो की उपस्थिति में विस्तार करने के लिए वे कुछेक छोटे – बड़े शहरों में लगभग 300 बिस्तर वाले और छोटे शहरों में 200 बिस्तर वाले अधिग्रहणों पर विचार कर रहे हैं।

हाल ही में अपोलो ने आईएचएच के साथ एक निश्चित शेयर खरीद समझौता हस्ताक्षर किया है जो अपोलो ग्लेनेईगल्स हॉस्पिटल लिमिटेड (एजीएचएल) में उसकी संयुक्त उद्यम साझेदार है। यह समझौता 410 करोड़ रुपये की नकद खरीद के मद्देनजर एजीएचएल में उसकी मौजूदा 50 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए था।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित क्यूआईपी 24/7 डिजिटल ऐप में निवेश और लाभप्रदता में वृद्धि के लिए ऋण कम करने की खातिर प्रस्तावित अधिग्रहणों में वित्त पोषण के लिए होगा।

मैक्स फाइनैंशियल को शेयर बदला-बदली के लिए डीईए की मंजूरी मिली

सुब्रत पांडा
मुंबई, 19 नवंबर

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की पैतृक कंपनी मैक्स फाइनैंशियल सर्विसेज (एमएफएसएल) को मैक्स लाइफ में मित्सुई सुमितोमो की हिस्सेदारी को कंपनी के शेयरों के साथ बदलने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) से मंजूरी मिल गई है।

यह सौदा एमएफएसएल में 21.9 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में मित्सुई सुमितोमो की 20.6 प्रतिशत हिस्सेदारी की अदला-बदली से जुड़ा हुआ है जिसके फलस्वरूप जीवन बीमा कंपनी में एमएफएसएल की हिस्सेदारी 93 प्रतिशत से ज्यादा हो जाएगी। एमएफएसएल 7.54 करोड़ शेयर आवंटित करेगी, जो समझौते के अनुसार मित्सुई सुमितोमो के लिए चुकता शेयर पूंजी के 21.87 प्रतिशत के बराबर है।

कंपनी ने कहा है, ‘भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की मंजूरी मिलने के साथ यह सौदा पूरा हो जाएगा।’

बीएसई पर एमएफएसएल का शेयर 1.06 प्रतिशत घटकर 612.55 रुपये पर बंद हुआ। मौजूदा समय में मैक्स लाइफ में एमएफएसएल की 72.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है और जीवन बीमा कंपनी में एमएसआई की 25.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।